12.00 NOON

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री गुलाम नबी आज़ादः एक question इन्होंने यहां उठाया। ...(**व्यवधान**)... सरकार और पार्टी को एक भाषा में बोलना चाहिए - कोई कहता है कि हमने किया, कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب غلام نبی آزاد:** ایک کوئیشچن انہوں نے یہاں اٹھایا ...(مداخلت)... سرکار اور پارٹی کو ایک بھاشا بولنا چاہیئے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کیا، کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, as there is no time,

आप नाम नोट करके सभी माननीय सदस्यों को लिखित रूप में उत्तर भेज दीजिए। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद।

श्री राजनाथ सिंहः धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... The Home Minister has taken note of all the suggestions and also the clarifications. Please go through it. I really feel sorry that I could not allow the Home Minister earlier. Normally it does not happen, but today, at least, we had an opportunity to hear the Home Minister. Many doubts have been clarified but still there are some doubts in the minds of the hon. Members. So, please take care of them and then send them answer. Question Hour. ...*(Interruptions)*... Question No.181. Mr. Minister. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बैठ जाइए।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, at 1 o'clock. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Today is Friday. ...*(Interruptions)*... Please. What can I do? ...*(Interruptions)*... I have been cautioning the hon. Members. ...*(Interruptions)*... All the hon. Members, who want to go, please go quietly. ...*(Interruptions)*... If you want to remain, please remain quietly. ...*(Interruptions)*.. Please.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Subsidy for sugar sector

*181.SHRI T. RATHINAVEL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has approved a subsidy of ₹5.5 per quintal of sugarcane crushed during the 2017-18 season to help sugar mills clear more than ₹ 19,000 crore dues to cane growing farmers;

---

†Transliteration in Urdu script.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the assistance would be paid directly to farmers on behalf of mills; and

(d) whether the subsidy would be adjusted against the Fair and Remunerative Price of 255 per quintal fixed by Government as the rate that mills must pay to cane growing farmers as well as the arrears of payments pending from various years?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAMVILAS PASWAN): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) With a view to improve the liquidity position of the sugar mills to enable them to clear cane dues of farmers and to offset the cost of cane, the Central Government has extended assistance @ ₹ 5.50/quintal of cane crushed amounting to about ₹ 1540 crore.

(c) and (d) The assistance shall be paid directly to the farmers on behalf of the mills and be adjusted against the cane price dues payable to the farmers including arrears of previous seasons.

SHRI T. RATHINAVEL: Respected Chairman, Sir, the Indian sugar industry is already facing problems to clear arrears of cane growers and the sugar industry is also facing difficulties to realise the cost of their production. It is estimated that India's sugar production this year will touch 360 lakh metric tonnes and liquidating this will be a daunting task for them. In the meanwhile..

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary, Rathinavel*ji*? *...(Interruptions)...* Please.

SHRI. T. RAHINAVEL: In the meanwhile, India has imported about 30,000 quintals of sugar from Pakistan which is quite cheaper than the Indian sugar. This import, if continued, will have a serious repercussion on the Indian sugar industry which provides lakhs of people employment and helping sugarcane growers. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps by the Government to protect the domestic sugar from cheap import of sugar from the neighbouring countries, including Pakistan.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से यह चिंता जताई है कि भारत में चीनी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है और यह बात सही है कि 2017-18 में हमारे देश में 316 लाख टन नहीं बल्कि लगभग 322 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। यह भी सही है कि जब उत्पादन कम होता है, तब भी चीनी का आयात होता है, निर्यात भी होता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान या अन्य देशों से देश के अंदर जो चीनी आ रही है, वह हर साल 20 लाख टन के आसपास आयात होती है और हम 25 से 26 लाख टन चीनी का निर्यात भी करते हैं। जहां तक यह सवाल है कि हमारी चीनी का भाव ज्यादा कम न हो जाए, माननीय सदस्य ने यही प्रश्न पूछा था कि काश्तकारों को पैसा मिल जाए, इसी कारण से यह साढ़े पांच रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फार्मर्स को पेमेंट करने के लिए दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Right. Second supplementary.

SHRI T. RATHINAVEL: Respected Chairman, Sir, Tamil Nadu sugar industry has been passing through a difficult period as it has been hit by record low production following the failure of monsoon. The capacity utilisation for sugar mills in Tamil Nadu slumped to 25 per cent during the current season and that the cost of production has also gone up heavily. With low sugar prices, sugar mills in Tamil Nadu could neither pay the fair and remunerative price on time nor service nor repay the loans. So, it has been demand of sugar mills in Tamil Nadu that they should be exempted from export obligations.

MR. CHAIRMAN: Right. Are you exempting them from export obligations? ...*(Interruptions)*... This is not the system; you have to come to the operative part every time. In the beginning, it is okay.

श्री सी.आर. चौधरी: माननीय चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि because of failure of the monsoon तमिलनाडु में गन्ने का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। वास्तव में पिछले दो-तीन साल से मानसून failure के कारण प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और इसके साथ ही साथ इसका sowing area भी कम हो रहा है, यह बात सही है। यहां पर 36 मिलें हैं, उनमें से 26 मिलें काम कर रही हैं, उसके मुकाबले they are not getting the raw material, they are not getting the sugarcane. अब जहां तक माननीय सदस्य का यह मानना है, I would say that इस संबंध में पूरे देश की यही स्थिति है, इसलिए पूरे देश में sugar producing जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सबको हमने साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल का फायदा दिया है। फैक्टरी गेट पर जो मिनिमम 29 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार यह रेट फिक्स किया गया है, इसे not below ₹ 29 किया गया है। इसी प्रकार से subvention of interest है। इसमें ई.बी.पी. को एथनॉल बनाने के लिए काफी छूट दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि कई प्रकार से relaxations दिए गए हैं, ताकि फैक्टरी वालों को...

श्री सभापति: उनका सवाल है कि are you going to give them exemption from export obligation?

SHRI C.R. CHAUDHARY: It is not possible.

श्री विजय पाल सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, उन्होंने एथेनॉल बनाने की भी बात की। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की गन्ने के बकाये की बड़ी भारी समस्या है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मिलों को साढ़े पांच रुपए incentive दिया है। मैं इसे मिलों के लिए incentive कहूंगा, क्योंकि यह किसान का नहीं है, किसानों को तो पूरा उतना ही मिलना है।

श्री सभापतिः आप अपना सवाल पूछिए।

श्री विजय पाल सिंह तोमरः सर, सरकार का 1,540 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, सरकार 30 लाख मीट्रिक टन के लिए bufferstock भी बना रही है। सरकार ने गन्ने के रस से बनने वाले एथेनॉल के लिए साढ़े चार हजार करोड़ रुपए दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो एथेनॉल गन्ने के रस से बनेगा, उसे दस प्रतिशत तक पेट्रोल में मिलाने की कोई योजना है?

श्री सी.आर. चौधरीः सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो एथेनॉल बनाया जा रहा है, वह वास्तव में पेट्रोल में मिक्स करने के लिए ही बनाया जा रहा है। हमारा इसे 10 प्रतिशत तक करने का इरादा है, जबकि अभी चार प्रतिशत तक पहुंच गया है, इस कारण एथेनॉल बनाने की परमिशन दी गई है। पहले ethanol molasses 6 कैटेगरीज़ का था, उसके बाद हम 'सी' और 'बी' category के molasses को काम में ले रहे हैं और उनकी परमिशन दे दी गई है।

कुमारी शैलजाः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हरियाणा में हजारों किसानों को बार-बार धरने पर बैठना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनके dues समय पर नहीं मिलते और इतने dues हो जाते हैं कि उन्हें बार-बार धरने पर बैठना पड़ता है। मंत्री जी, क्या यह बताएंगे कि हरियाणा के कितने farmers के dues अभी बकाया हैं? अभी किसानों का कितना amount बकाया है, कितने farmers के बकाया हैं? खासकर यमुना नगर और अंबाला क्षेत्र में कितने किसानों के बकाया हैं? इस सवाल में पूछा गया है कि 19,000 करोड़ due हैं और आपने कहा कि इस वष आप सिर्फ 1540 करोड़ रुपए देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। माननीय मंत्री जी, खासकर हरियाणा के बारे में बताएं।

श्री सभापतिः मंत्री जी, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप नोट करके बाद में बता दें। अगर अभी बता सकते हैं, तो बताइए।

श्री रामविलास पासवानः सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो रेट्स होते हैं, एक एफ.आर.पी. होता है और दूसरा एस.ए.पी. होता है। जहां तक हरियाणा के वर्ष 2017-18 के बकाये का सवाल है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो एफ.आर.पी. रेट फिक्स किया है, उसके मुताबिक किसानों का बकाया ज़ीरो है। एस.ए.पी., जिसको राज्य सरकारें तय करती हैं, उसके मुताबिक किसानों का बकाया 693 करोड़ है। इस प्रकार, वर्ष 2016-17 में जो बकाया था, वह सारा का सारा भुगतान हो चुका है।

प्रो. राम गोपाल यादवः सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में चीनी का जो उत्पादन हुआ है, वह खपत से ज्यादा हुआ है। इसके बावजूद, गवर्नमेंट ने चीनी को इम्पोर्ट किया है। चीनी आज देश में surplus है और surplus होने के बाद भी उसका import किया गया, जिसकी वजह से मिलों की भी स्थिति खराब हुई और किसानों का जो लगभग 22 हजार करोड़ रुपया बकाया था, उसको मिल अदा नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पर्याप्त मात्रा में चीनी यहां उपलब्ध है, तो वह import क्यों कराई जाती है और उस import करवाने की वजह से किसानों को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, मिलों की हालत खराब हो गई है, उसको सुधारने के लिए आप क्या काम करेंगे? क्या आप चीनी को एक्सपोर्ट करने की कोई व्यवस्था करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इम्पोर्ट लगातार बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है। ऐसा होने के जो भी कारण हैं, उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री सी.आर. चौधरीः माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 के लिए हमारा प्रोडक्शन काफी कम हुआ। वह 202 लाख टन तक हुआ, जबकि इससे पहले वह करीब दो-ढाई लाख टन था और उससे पहले वह 285 लाख टन भी था, जो कि अभी बढ़कर 322 लाख टन हो गया, तो यह variation प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है। जब प्रोडक्शन कम होता है, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट इस बात की चिन्ता करती है। जब चीनी का भाव 40 रुपए किलो से क्रॉस करने लग जाता है, then we have to import sugar from other countries, ताकि चीनी का भाव स्थिर रहे। यदि हम इम्पोर्ट नहीं करें और चीनी 50 रुपए किलो हो, then what will happen to consumers? तो यह भी देखना पड़ेगा।

श्री रामविलास पासवानः सभापति जी, माननीय राम गोपाल जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में इन्होंने पहले ही बतला दिया है कि 322 लाख टन हमारी पैदावार हुई है, 40 लाख टन carry forward है, उसमें से 30 लाख टन हम बफर स्टॉक के लिए रख रहे हैं और हमने कहा है कि 20 लाख टन का एक्सपोर्ट किया जाए। उसके बावजूद, हमें नवम्बर से लेकर दो महीने के लिए 20 लाख टन के हिसाब से रखना पड़ता है और उसके बाद भी कुल मिलाकर 12 लाख टन बचता है। आपने जो कहा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास एक ही हथियार है कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। पहले इम्पोर्ट ड्यूटी 50 परसेंट थी, उसमें relaxation देकर हमने ज़ीरो परसेंट कर दिया है। उसके बावजूद, यह देखना आवश्यक है कि हम कंट्री-वाइज़ नहीं चलते हैं कि एक कानून किसी एक कंट्री के लिए बनाएं और पाकिस्तान के लिए दूसरा बनाएंगे। हमने जो relaxation दिया है, वह 100 परसेंट दिया है। सरकार इम्पोर्ट नहीं कर रही है, यह ओपन मार्केट में कितनी चीनी रिलीज़ हो, बफर स्टॉक बनाने का काम हो, जिससे किसानों को पैसा मिले। किसानों को पैसा तभी मिलता है, जब मिल-मालिक घाटे में नहीं चलता है। इसलिए हम मिल-मालिक को घाटे में नहीं रहने देना चाहते हैं और किसान को पेमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मिल-मालिक पेमेंट नहीं करता है, तो यह राज्य सरकार की जवाबदेही होती है कि वह उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।